भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 34
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सुपारी किसानों की फसल का नुकसान

***34. श्री राजमोहन उन्नीथनः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कासरगोड जिले में सुपारी किसानों को पत्ती धब्बा (लीफ स्पॉट) रोग के कारण भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से रोग प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देने और सीमावर्ती जिले के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘सुपारी किसानों की फसल का नुकसान’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) एवं (ख) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क)**:** केरल राज्य सरकार ने ‘कासरगोड जिले में सुपारी की खेती’ की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आईसीएआर-केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड (आईसीएआर-सीपीसीआरआई) को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया था। इस टीम ने कासरगोड जिले के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और लीफ स्पॉट रोग के कारण उपज में 5% से 20% तक की हानि का अनुमान लगाया।

इसके अलावा, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस) का एकीकृत कीट प्रबंधन-सह-टिड्डी प्रभाग, देश भर में स्थित अपने 47 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी) और टिड्डी-सह-केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (एलसीआईपीएमसी) के माध्यम से सर्वेक्षण और निगरानी करके कीटों और रोगों की स्थिति का आकलन करता है। सीआईपीएमसी एर्नाकुलम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, केरल के सुपारी उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कासरगोड जिले में, सुपारी के बागानों में लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप ट्रेस ईंटेंसिटी लेवल पर देखा गया है, जबकि आर्थिक सीमा स्तर (ईटीएल) से ऊपर रोग की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस संबंध में विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

हालाँकि, सीआईपीएमसी केरल के प्रमुख सुपारी उत्पादक क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी के माध्यम से सुपारी के बागानों की निरंतर निगरानी करता है ताकि सुपारी के कीटों और रोगों का शीघ्र पता लगाने और उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख): राष्ट्रीय स्तर पर सुपारी के समग्र विकास का समन्वय, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), कालीकट द्वारा किया जाता है। सुपारी किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, डीएएसडी ने फसल प्रबंधन हेतु उन्नत तकनीकों के प्रसार हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की हैं:

- फ्रंटलाइन प्रदर्शन (एफएलडी) भूखंडों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके मौजूदा सुपारी बागानों में बहु-प्रजाति फसल को बढ़ावा देना।
- कर्नाटक के 10 एलएसडी प्रभावित सुपारी उत्पादक तालुकों में प्रभावित क्षेत्र के चयनित किसानों के खेतों में वर्ष 2024-25 तक सुपारी में लीफ स्पॉट रोग (एलएसडी) के समुदाय-आधारित प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन स्थापित करना। यह कार्यक्रम प्रत्येक तालुका में 5 हेक्टेयर सहित 50 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जिसका उद्देश्य एलएसडी के नियंत्रण के लिए अनुशंसित वैज्ञानिक प्रबंधन उपायों का प्रचार-प्रसार करना है।
- केरल और कर्नाटक के चयनित क्षेत्रों में सुपारी में फ्रूट रोट रोग के प्रबंधन में नए फंगिसाइड मैंडीप्रोपामिड के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एफएलडी स्थापित करना।
- सुपारी में रूट ग्रब के प्रबंधन में ईपीएन (एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड) के उपयोग का प्रचार-प्रसार करने के लिए एफएलडी स्थापित करना।
- सुपारी की बौनी संकर किस्मों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन।
- सुपारी में वाईएलडी प्रबंधन में प्लास्टिक मल्चिंग के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एफएलडी।

- रोग का अनुमान लगाने में सहायता के लिए मौसम और सुपारी के लीफ स्पॉट रोग के बीच संबंध का अध्ययन करने हेतु आईसीएआर-सीपीसीआरआई को एक तापमान और सापेक्ष आर्द्रता नियंत्रक इकाई प्रदान की गई है।

सरकार लीफ स्पॉट रोग (एलएसडी) और येलो लीफ रोग (वाईएलडी) जैसे रोगों के प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप करती है। सुपारी खेती के दौरान कोलेरोगा, येलो लीफ रोग और लीफ स्पॉट रोग जैसे व्याप्त रोगों के कारण कृषक समुदाय बहुत अधिक परेशान है। वर्ष 2006-07 में, भारत सरकार ने 9541 हेक्टेयर क्षेत्र में येलो लीफ रोग (वाईएलडी) से प्रभावित सुपारी के बागानों के पुनर्वास/पुनर्रोपण कार्यक्रम के लिए केरल राज्य को 1170.83 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी। वर्ष 2022 में, कर्नाटक में सुपारी के बागान एलएसडी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था।

इस मुद्दे के समाधान के लिए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक में वाईएलडी तथा एलएसडी जैसी बीमारियों और सुपारी के अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए सुपारी पर एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति (एनएससी) का गठन किया। वाईएलडी के लिए, वाईएलडी सहनशील पाम की पहचान और ऊतक संवर्धन के माध्यम से इसके प्रसार की एक दीर्घकालिक कार्यनीति तैयार की गई है। एनएससी ने सुपारी में एलएसडी के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है।

क. पादप स्वच्छता: जहाँ तक संभव हो, गंभीर रूप से संक्रमित निचली पत्तियों को हटाकर जला देना।
ख. फंगीसाइड का छिड़काव:

i. मानसून (जुलाई-अगस्त) के दौरान गुच्छों पर छिड़काव करते समय पत्तियों पर बोर्डो मिश्रण (1%) का छिड़काव किया जा सकता है।

ii. यदि रोग सितंबर-अक्टूबर के दौरान दिखाई दे, तो पहले छिड़काव के लिए प्रोपिकोनाज़ोल 25% ईसी (1 मिली प्रति लीटर पानी) या टेबुकोनाज़ोल (1 मिली प्रति लीटर) का छिड़काव किया जा सकता है, इसके बाद रोग की गंभीरता के आधार पर 25-30 दिनों पर प्रोपिनेब 70% डब्ल्यूपी (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का दूसरा छिड़काव किया जा सकता है। 200 लीटर घोल में 100 मिली सर्फेक्टेंट/स्टिकर घोल में मिलाए जा सकते हैं।

ग. पोषक तत्व का प्रबंधन: पौधौं के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा प्रभावित पाम के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी के परीक्षण पर आधारित संतुलित पोषक तत्व का प्रबंधन किया जाना चाहिए।

एनएससी की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने बागवानी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, सुपारी में लीफ स्पॉट रोग के प्रबंधन के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम), कर्नाटक को 3700 लाख रुपये मंजूर किए। राज्य बागवानी मिशन कर्नाटक से वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना में एलएसडी के प्रबंधन के लिए आवश्यक शेष राशि को शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है। डीएएसडी ने वर्ष 2024-25 से कर्नाटक के 10 एलएसडी प्रभावित सुपारी उत्पादक तालुकों में प्रभावित क्षेत्र के चयनित किसानों

के खेतों में सुपारी में लीफ स्पॉट रोग के समुदाय-आधारित प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन स्थापना की। यह कार्यक्रम प्रत्येक तालुका में 5 हेक्टेयर सहित 50 हेक्टेयर को कवर करता है, जिसका उद्देश्य एलएसडी के नियंत्रण के लिए सिफारिश की गई वैज्ञानिक प्रबंधन उपायों का प्रचार-प्रसार करना है। इस कार्यक्रम के लिए 03 वर्ष हेतु 6.316 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल मौसम से होने वाली फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस), केंद्रीय क्षेत्र सूचकांक आधारित फसल बीमा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कासरगोड जिले में सुपारी पहले से ही इस स्कीम के अंतर्गत कवर की गई है, जिसमें कीटों से सुरक्षा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, इस स्कीम के तहत 2620 किसानों के आवेदन नामांकित किए गए और कासरगोड जिले में सुपारी किसानों के 2618 आवेदनों के लिए 3,00,75,802 रुपये के दावों का निपटान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कासरगोड जिले में सुपारी फसल के तहत नामांकित आवेदनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई है।

अनुबंध-I

डीपीपीक्यूएस, डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा सुपारी फसल पर किए गए विशेष सर्वेक्षण/निगरानी का विवरण

वर्ष	फसल	जिला	सर्वेक्षित क्षेत्र (विशेष सर्वेक्षण)	रोग	रोग की तीव्रता
2023-24	सुपारी	**कासरगोड**	200	पत्तियों का पीला पड़ना (पादपों का कायिक विकार)	पता लगाकर
2025-26	सुपारी	**कासरगोड**	161	पत्तियों का पीला पड़ना (पादपों का कायिक विकार)	पता लगाकर
				फ्रूट रोट (फाइटोफ्थोरा पामिवोरा)	पता लगाकर
				लीफ स्पॉट/लीफ रोट (कोलेटोट्राइकम ग्लोएस्पोरियोइड्स)	पता लगाकर

*****